

बंगाल में प्रोटोकॉल तोड़कर दुकान पर पहुंचे पीएम मोदी, बच्चों को भी खिलाया

संवाददाता कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग और सहज अंदाज झाड़ग्राम में देखने को मिला। चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद एसपीजी की भारी सुरक्षा तोड़ प्रोटोकॉल से बाहर निकल कर प्रधानमंत्री मोदी अचानक सड़क किनारे स्थित एक दुकान पर रुक गए। इस दौरान उन्होंने झालमुड़ी (चावल का भुजा जो तेल प्याज और मिर्ची मिलाकर बनाया जाता है) का स्वाद लिया, बच्चों और महिलाओं को खिलाया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री के अचानक रुकने से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी भी कुछ क्षणों के लिए चौंक गए, जबकि स्थानीय लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे थे। झाड़ग्राम में जनसभा समाप्त करने के बाद वह अपने हेलीकॉप्टर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सड़क किनारे लगी एक



झालमुड़ी की दुकान देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला रुका, मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रधानमंत्री वाहन से उतरकर सीधे दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से झालमुड़ी बनाने को कहा। दुकानदार ने मुरमुआ, मसाला, मिर्च, तेल और अचार मिलाकर झालमुड़ी तैयार की। प्रधानमंत्री ने पहले वहां मौजूद कुछ बच्चों को खिलाया, उसके बाद स्वयं भी झालमुड़ी खाई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग जय श्री राम

और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री लोगों के बीच सहज भाव से दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह स्थानीय महिलाओं से बातचीत करते और हालचाल पूछते भी नजर आए। महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी जताई बताया जा रहा है कि जिस दुकान पर प्रधानमंत्री रुके, वह बिहार के गया जिले के विक्रम साह की है। विक्रम साह पिछले 12 वर्षों से झाड़ग्राम में झालमुड़ी की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। अचानक काफिला रुका और प्रधानमंत्री उनकी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे अच्छी झालमुड़ी बनाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने मसालेदार झालमुड़ी तैयार की। विक्रम साह ने बताया कि झालमुड़ी खाने के बाद प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि स्वाद बहुत अच्छा है। दुकान पर मौजूद लोगों के लिए यह पल यादगार बन गया। प्रधानमंत्री ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस पल की तस्वीरें साझा कीं।

गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ से हालात बेकाबू

● लंबी कतारों से परेशान यात्रियों ने कूदी बाउंड्री

संवाददाता

सूरत। गर्मी की छुट्टियां, शादी का सीजन और फैक्ट्रियों में छुट्टियां घोषित होते ही गुजरात के सूरत में रहने वाले प्रवासी मजदूर अपने-अपने घर लौटने के लिए बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़े हैं। इसी के चलते उधना रेलवे स्टेशन पर हालात बेकाबू हो गए। इसके चलते स्टेशन पर भगदड़ जैसे दृश्य देखने को मिले। इससे निपटने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। यात्रियों की भारी भीड़ और ट्रेनों की कमी के कारण स्टेशन परिसर में हालात बेकाबू हो गए और अफरा तफरी मच गयी। यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर 12 से 24 घंटे तक लंबी कतारों में भूखे-प्यासे खड़े हुए हैं। धैर्य टूटने पर कई लोगों ने स्टेशन की बाउंड्री कूदकर अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे हालात बेकाबू हो गए। इस स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार स्टेशन पर पीने के पानी की भी भारी किल्लत देखी गई। जब प्रशासन ने पानी की व्यवस्था की गई, तो प्यासे लोग एक-दूसरे से पानी की बोतल भी छीनते नजर आए। इससे रेलवे स्टेशन के हालात का अंदाजा



लगाया जा सकता है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि स्टेशन पर यात्रियों की कतार 3 से 5 किलोमीटर तक लंबी हो गई थी। बताया जा रहा है कि यह भीड़ केवल गर्मी की छुट्टियों की वजह से नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय से एलपीजी सिलेंडर संकट के कारण भी मजदूरों का पलायन बढ़ा है। इससे यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है और रेलवे की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। सूत्रों का कहना है कि भीषण गर्मी और भीड़ के कारण लाइन में खड़े दो यात्री बेहोश भी हो गए। करीब 7000 से ज्यादा यात्रियों के सामने केवल 2 ट्रेनों की उपलब्धता से हालात और बिगड़ गए। इस दौरान एक भावुक दृश्य भी सामने आया, जहां एक युवक अपनी पत्नी की अस्थिरां लेकर घंटों ट्रेन में चढ़ने के लिए संघर्ष करता

रहा। यात्रियों का आरोप है कि हर साल इस तरह की भीड़ के बावजूद रेलवे प्रशासन पहले से कोई ठोस योजना नहीं बनाता, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार गर्मी के मौसम को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब तक 6 ट्रेनों का संचालन किया जा चुका है, जिनमें उधना से जयनगर और मधुबनी के लिए ट्रेनें शामिल हैं। यात्रियों की संख्या पर लगातार नजर रखी जा रही है। रेलवे डिप्टी एसपी दीपक गवाड़े ने बताया कि घोषित ट्रेनों के मुकाबले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि अनावश्यक रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं को भीषण गर्मी में स्टेशन पर न रोके।

केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ: ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई पंचमुखी डोली, 22 अप्रैल को खुलेंगे कपाट

संवाददाता

रुद्रप्रयाग। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की वार्षिक यात्रा के तहत भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली रविवार को शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर से विधिवत पूजा-अर्चना के बाद धाम के लिए रवाना हो गई। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच डोली के प्रस्थान के साथ ही क्षेत्र 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा। मंदिर परिसर को लगभग आठ कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो उठा। पूर्व परंपरा के अनुसार शनिवार रात्रि को भैरवनाथ जी की पूजा-अर्चना भी संपन्न की गई। डोली यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और कई भक्त पैदल ही यात्रा में सम्मिलित हुए। निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार डोली उखीमट से प्रस्थान कर गुफाकशी पहुंचेगी, जहां श्री विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन देने हेतु अल्प विश्राम किया जाएगा। इसके पश्चात



डोली फाटा के लिए प्रस्थान करेगी, जहां रात्रि विश्राम निर्धारित है। आगामी 20 अप्रैल को डोली फाटा से प्रस्थान कर गौरीकुंड स्थित गौरीमाई मंदिर पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। अगले दिन 21 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचकर मंदिर भंडार में विराजमान होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को प्रातः 08 बजे शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे, जिसके साथ ही यात्रा का औपचारिक शुभारंभ होगा। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और वीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क एवं पैदल मार्गों का सुदृढीकरण, बर्फ हटाने सहित सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ क्षेत्र की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके।

महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल



संवाददाता

नई दिल्ली। महिला आरक्षण पर 131 वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार शाम विपक्षी दलों पर लगाए गए आरोपों के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार महिला आरक्षण के पक्ष में है, तो 543 लोकसभा सीटों में एक-तिहाई यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि वह सदन में विधेयक लाकर महिला आरक्षण को प्रभावी बनाए और इसमें किसी प्रकार की शर्तें न रखे।

पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून का रास्ता साफ, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी

संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 'जागृत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि यह बड़ा कदम है और उन्होंने वाहेगुरु का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें यह सेवा करने का अवसर मिला, इसके लिए वह कृतज्ञ हैं और समूची सिख संगत का धन्यवाद करते हैं। हालांकि, फिलहाल यह कानून केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि वह सदन में विधेयक लाकर महिला आरक्षण को प्रभावी बनाए और इसमें किसी प्रकार की शर्तें न रखे।



अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 'स्वरूप' (पवित्र ग्रंथ) को जानबूझकर फाड़ना, जलाना या किसी भी तरह से खंडित करना, पवित्र ग्रंथ पर थूकना, उसे गंदे हाथों से छूना या किसी ऐसी जगह रखना जहां उनकी गरिमा भंग होती हो, गुरु साहिब के स्वरूप को सार्वजनिक रूप से फेंकना या गलियों/नालियों में लावारिस छोड़ देना, पवित्र स्वरूप को चोरी करना या उसे मर्यादा के विरुद्ध अपने पास रखना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में शराब, तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना या लेकर जाना, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से

पवित्र बाणी या गुरु साहिब के प्रति अभद्र टिप्पणी या अपमानजनक फोटो-वीडियो बनाना। इस कानून में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 20 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। इन अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है और इसमें सहयोग करने वालों को भी बराबर दोषी माना जाएगा। यह बिल 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसे राज्य में धार्मिक समझद्वारा बनाए रखने और बेअदबी के मामलों पर सख्ती से रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

कंगना रनौत ने नंदीग्राम में किया रोड शो, कहा-हर जगह केसरिया की रौनक



संवाददाता

नंदीग्राम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान का दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है उसी गति से प्रचार जोर पकड़ चुका है। इसी क्रम में रविवार को बालीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत ने पूर्वी मेदिनिपुर जिले के नंदीग्राम में रोड शो किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के लोग अन्याय को

कभी बर्दाश्त नहीं करते। पिछली बार ममता बनर्जी को यहां से खदेड़ दिया गया था और इस बार वह यहां से चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं। यही नंदीग्राम की ताकत है। केसरिया हर जगह दिखाई देता है। बंगाल चुनाव को लेकर बहुत उत्साह का माहौल है। उल्लेखनीय है कि, नंदीग्राम से वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्रु अधिकारी भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

एसआरए में बड़े सुधार: डॉ. महेंद्र कल्याणकर के नेतृत्व में तेज हुई पुनर्वसन प्रक्रिया

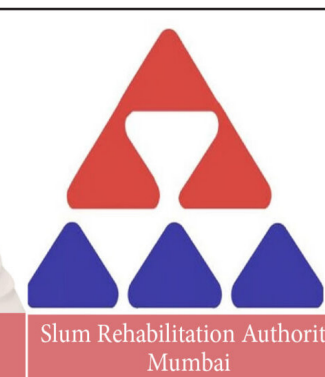
एसआरए के फैसलों से बदलेगी मुंबई के विकास की नई तस्वीर

संवाददाता

मुंबई। झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. महेंद्र कल्याणकर के नेतृत्व में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रक्रिया में बड़े और संरचनात्मक सुधार देखने को मिल रहे हैं। इन सुधारों का उद्देश्य मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाना और झोपड़पट्टी धारकों को उनके हक का सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराना है। मुंबई को वैश्विक स्तर पर विकसित शहर बनाने की परिकल्पना, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लंबे समय से व्यक्त करते रहे हैं, तभी साकार हो सकती है जब शहर में झोपड़पट्टी



समस्या का स्थायी समाधान हो। इसी दिशा में एसआरए के सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर ने तकनीक और पारदर्शिता पर आधारित कई अहम कदम उठाए हैं। सबसे प्रमुख पहल के रूप में शहर की सभी झोपड़पट्टियों का डिजिटल मैपिंग किया जा रहा है, जिससे पात्रता निर्धारण अधिक सटीक और पारदर्शी होगा। इसके साथ ही, नए अतिक्रमणों पर निगरानी के लिए 'नेत्रम (NETRAM)' प्लेटफॉर्म



शुरू किया गया है, जो उपग्रह चित्रों के माध्यम से अवैध निर्माणों की पहचान करता है। प्रशासनिक स्तर पर एसआरए की लगभग 22 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे नागरिकों और डेवलपर्स को मंजूरी प्रक्रिया में तेजी मिली है। फाइल ट्रैकिंग और रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक तथा नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित चैटबॉट्स भी लागू किए गए

हैं। नीतिगत सुधारों के तहत, लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए 45 दिनों के भीतर निष्कासन की मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू की गई है। साथ ही, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पात्र झोपड़पट्टीधारकों के लिए आवास का आकार 269 वर्ग फुट से बढ़ाकर 300 वर्ग फुट कर दिया गया है, जिसे अब पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। जो पुनर्वसन नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। डेवलपर्स के लिए भी स्व-प्रमाणन (Self-Certification) और हप्ते आधारित नीति (Instalment Policy) जैसे सुधार लागू किए गए हैं, ताकि परियोजनाओं की गति बढ़ाई जा सके और निवेश को प्रोत्साहन मिले। इसी क्रम में, उन विकासकों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है जो झोपड़पट्टी धारकों को समय पर भाड़ा (Rent) नहीं दे रहे हैं। इसके लिए एसआरए ने ऑनलाइन शिकायत

प्रक्रिया लागू की है, जिससे प्रभावित नागरिक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, विकासकों को एडवांस भाड़ा (Advance Rent) समय पर देने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि पुनर्वसन के दौरान किसी भी परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से मेंटेनेंस फंड (Corpus Fund) को लेकर भी बदलाव प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रति लाभार्थी 40,000 जमा करना अनिवार्य है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख से 3 लाख तक करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि पुनर्वसन इमारतों का दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित हो सके और झोपड़पट्टी धारकों पर जातिगत आर्थिक बोझ न पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से एसआरए परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, अतिक्रमण पर नियंत्रण मजबूत होगा और मुंबई में पुनर्वसन प्रक्रिया को नई गति मिलेगी।

संपादकीय

आखिर कब तक छली जाती रहेंगी नारियां!

सत्ता और पौरुष बल ने हमेशा ही नारियों को कमजोर समझकर 'भोग्या वस्तु' माना है। मर्द की इसी मानसिकता से कलांत होकर कवयित्री को लिखना पड़ा— 'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी'। यहां तक कि अंबेडकर के नाम पर यह भी प्रचारित किया गया कि उन्होंने महिलाओं को राजनीति में लाने का विरोध करते हुए कहा था कि महिलाएं घर-आंगन बुहारने, भोजन बनाने, बर्तन-कपड़े साफ करने और बच्चा जनने के लिए हैं, उन्हें आंगन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सहस्राब्दियों से नारियां सत्ता द्वारा छली जाती रही हैं। सती सावित्री को यमराज ने, अहिल्या को इंद्रदेव ने और सीता को त्रैलोक्य विजयी रावण ने छला। आज भी सत्ता में बैठे 'भूखे भेड़ियों' द्वारा महिलाओं का शील-हरण किया जा रहा है।

मोदी सरकार ने 'नारी सशक्तिकरण' का नारा वर्षों से बुलंद किया है, लेकिन पिछले बारह वर्षों में लाखों महिलाएं और नाबालिग बच्चियां गायब हुईं। दर्जनों पत्नियों द्वारा प्रेमियों के साथ मिलकर हत्याएं कराई गईं। सत्ताधारी दल के विधायकों और पदाधिकारियों के विरुद्ध बलात्कार के आरोप लगे। 'गेरुआ वस्त्र' और 'आध्यात्म' की आड़ में पाखंडी बाबाओं द्वारा नारियां प्रताड़ित हुईं। यहां तक कि शिक्षण संस्थानों में भी छात्र-छात्राओं के साथ दुष्कर्म की खबरें अनवरत आती रहती हैं। बाबाओं द्वारा महिलाओं की खरीद-फरोख्त के वीडियो सामने आते हैं और शिष्याओं के बलात्कार के दोषी जेल भेजे जाते रहे हैं, जिन्हें बचाने का प्रयास अक्सर सत्ता द्वारा ही किया जाता है। मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि एक महिला जिलाध्यक्ष ने अपनी ही 14 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार कराया। बल और पद के मद में चूर मर्द कब दरिद्र बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।

प्रधानमंत्री के 'राष्ट्र के नाम संबोधन' में महिला चिंता से अधिक चुनावी चिंता की झलक मिली। संसद में महिला आरक्षण के साथ-साथ सीटों की संख्या बढ़ाने के बिल पेश किए गए। जब 543 सांसद पहले से ही जनता पर बोझ हैं, तो उन्हें 850 करने के प्रस्ताव की क्या आवश्यकता थी? विपक्ष पर दोष मढ़ना महिलाओं में भ्रम पैदा करने की कोशिश प्रतीत होती है, ताकि विपक्षी दलों को 'महिला विरोधी' सिद्ध करके वोट हासिल किए जा सकें। दरअसल, महिला आरक्षण की नींव पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में 64वें और 65वें संशोधन बिल के जरिए रखी थी, जिसे 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी रूप दिया गया। इससे जमीनी स्तर पर (पंचायतों और नगर पालिकाओं में) 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ। तत्कालीन समय में आज की सत्ता में बैठे दलों ने राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण इसे अटका दिया था। मनमोहन सिंह सरकार ने 9 मार्च 2010 को 108वां संविधान संशोधन लाकर लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया था। फिर मोदी सरकार द्वारा 2029 के लाभ के लिए 2026 में विधेयक लाने का क्या औचित्य था? विशेषकर तब, जब 2023 में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया जा चुका था। 16 अप्रैल 2026 को फिर से बिल पेश करना चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है। सरकार जानती थी कि उसके पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है, फिर भी बिल लाया गया ताकि विपक्ष द्वारा रोके जाने पर उन्हें 'महिला विरोधी' करार दिया जा सके। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद विशेष सत्र बुलाना मर्यादाओं का उल्लंघन है। सच तो यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ दरिद्रता की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। 'डबल इंजन' की सरकारें इन्हें रोकने में विफल रही हैं, इसलिए सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसे बिल लाए जा रहे हैं। विपक्ष नारी विरोधी नहीं है, बल्कि वह बीजेपी की अवसरवादिता का विरोधी है। बहुमत के घमंड में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटना और विपक्षी सांसदों को निलंबित करके कानून पारित कराना लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है।

मप्र के अनूपपुर में ट्रैक्टर पलटने से 4 की मौत, गांव में पसरा मातम

संवाददाता

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में रविवार सुबह एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिससे सभी युवक उसके नीचे दब गए। बताया गया कि डिंडोरी जिले के रहने वाले चार दोस्त ट्रैक्टर से गिट्टी लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार डिंडोरी जिले के करंजिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीमकुंडी के रहने वाले चार युवक ट्रैक्टर लेकर अनूपपुर के पौनी गांव की ओर जा रहे थे। उनका उद्देश्य क्रेशर से गिट्टी लाना था। सुबह करीब छह बजे करन पटार थाना क्षेत्र के टाड़ पाथर के पास अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर सड़क से नीचे उतरकर गड्ढे में जा पलटा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे दबते ही सभी युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर थी। ट्रैक्टर का इंजन और भारी हिस्सा युवकों के ऊपर ही था, जिससे उन्हें निकालना



बेहद मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन बुलवाई और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान अंकुश उड्डे (24), ब्रजेश पेंडे (18), रवींद्र कुमार गोयल और 15 वर्षीय प्रकाश मार्को के रूप में हुई है। इनमें से एक युवक नाबालिग भी था। सभी मृतक भीमकुंडी गांव के निवासी थे और आपस में अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। चार युवकों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और हर किसी की आंखें

मामले को लेकर अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने बताया कि सभी मृतक डिंडोरी जिले के निवासी थे और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मार्ग कायम कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है, हालांकि तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही जैसे पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही जा रही है।

रक्षा मंत्री 21 अप्रैल को जर्मनी के दौरे पर जाएंगे

संवाददाता

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को जर्मनी के दौरे पर जाएंगे। वह अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और सरकार के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोनों रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान प्रशिक्षण में सहयोग के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रक्षा मंत्री का यह तीन दिवसीय दौरा रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसे उभरते हुए डोमेन में मौके तलाशने पर फोकस होगा। यह दौरा दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा करने और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच तालमेल के नए रास्ते पहचानने का मौका देगा। इस दौरान मेक-इन-इंडिया पहल के तहत



संयुक्त विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से जर्मन उद्योग प्रतिनिधियों से भी बातचीत होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री का यह जर्मन दौरा सात साल के बाद हो रहा है। इससे पहले भारतीय रक्षा मंत्री का जर्मनी का पिछला दौरा फरवरी, 2019 में निर्मला सीतारमण ने किया था। मिस्टर बोरिस पिस्टोरियस जून, 2023 में भारत आए थे और उन्होंने

राजनाथ सिंह के साथ लंबी बातचीत की थी। भारत और जर्मनी के बीच एक मजबूत और कई रणनीतिक साझेदारी है, जो लोकतांत्रिक मूल्य, कानून के राज और नियम-आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एक जैसी प्रतिबद्धता पर आधारित है। भारत के साथ हाल के वर्षों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग इस साझेदारी का अहम हिस्सा बनकर उभरा है।

उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को सौंपे 4000 आवास

संवाददाता

कोलंबो/ नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कोलंबो में आयोजित एक सामुदायिक स्वागत समारोह में उपराष्ट्रपति ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की।



विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरान, उपराष्ट्रपति ने उत्तरी रेलवे लाइन पर रेल सेवाओं की बहाली और तीन नए बेली पुलों के निर्माण की घोषणा की,

जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क बहाल करने में मील का पत्थर साबित

होगे। इसके अलावा, भारतीय आवास परियोजना (चरण-3) के तहत निर्मित

4000 आवास इकाइयों के अंतिम समूह को वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को सौंपा। भारत सरकार ने अब तक श्रीलंका में तमिल समुदाय को 50 हजार घर उपलब्ध कराए हैं और भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के तहत अतिरिक्त 10 हजार घर वितरित किए जाएंगे। भारत सरकार ने ओसीआई कार्ड के लिए पात्रता मानदंडों का विस्तार किया है। अब श्रीलंका में रह रहे पांचवीं और छठी पीढ़ी के भारतीय मूल

के तमिल भी ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। उपराष्ट्रपति ने कोलंबो में श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजित प्रेमदासा ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापारिक रिश्तों में विस्तार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारतीय लोकतंत्र और महिला आरक्षण की अधूरी यात्रा

विवेक रंजन श्रीवास्तव

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और समावेशिता है लेकिन जब लोकसभा में ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का संविधान संशोधन वर्षों तक पारित नहीं हो सका, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारा लोकतंत्र वास्तव में आधी आबादी को बराबरी का अवसर देने की इच्छा रखता है। महिला आरक्षण विधेयक केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं था, बल्कि यह भारतीय राजनीति में समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम होता। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटें मिलतीं तो उनकी आवाज अधिक मजबूती से गूँजती। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर नीतियाँ अधिक संवेदनशील और व्यावहारिक बनतीं। आज भी संसद में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत से कम है। यह आँकड़ा बताता है कि लोकतंत्र में



महिलाओं की भागीदारी कितनी सीमित है। आरक्षण से यह अंतर मिटाने का अवसर मिलता। विधेयक पारित न हो पाने के पीछे कई कारण रहे जिनमें राजनीतिक असहमति प्रमुख हैं। कुछ दलों ने जनगणना आधारित सीटों के पुनर्वितरण (परिसीमन) पर आपत्ति जताई। सपा जैसे कुछ दलों को आशंका थी कि आरक्षण से उनके पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होगा, इसलिए वे विरोध में रहे। ऐसे कई

कारणों ने मिलकर एक ऐतिहासिक अवसर का गर्भपात कर दिया। 2023 में लंबे संघर्ष और बड़ी बहस के बाद संसद ने आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया था। इसमें और प्रावधान हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटें मिलेंगी, लेकिन यह आरक्षण परिसीमन (delimitation) और जनगणना के बाद ही लागू होगा। इस शर्त ने

इसे एक अधूरी जीत बना दिया है, क्योंकि वास्तविक प्रभाव तब तक नहीं दिखेगा जब तक नई जनगणना और सीटों का पुनर्वितरण पूरा नहीं होता। 2024 के आम चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी, लेकिन प्रतिनिधित्व अब भी सीमित रहा। महिला संगठनों ने 2023 के विधेयक को "ऐतिहासिक लेकिन अधूरा" कहा। कई राजनीतिक दलों ने इसे समर्थन दिया, पर साथ ही यह मांग भी उठी कि इसे शीघ्र लागू किया जाए ताकि केवल कागजी प्रावधान न रह जाए। पहले महिला आरक्षण विधेयक का अधूरा रहना और फिर विलंबित रूप से पारित होना कई स्तरों पर असर डालता है। महिला नेतृत्व का अवसर फिलहाल टल गया लगता है। महिला संगठनों और नागरिक समाज में गहरी प्रतिनिधित्व देना भारतीय लोकतंत्र को अधिक सशक्त, न्यायपूर्ण और संतुलित बनाएगा और आज नहीं तो कल यह होकर रहेगा, क्योंकि यही पराजय नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र

की अधूरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राजनीति व्यापक राष्ट्रहित से बड़ी सिद्ध हुई। जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी, तब तक नीतियाँ समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएँगी। भारत की आधी आबादी को बराबरी का अधिकार देना केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। वर्तमान परिस्थितियाँ हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी राजनीति वास्तव में समावेशी है। महिला आरक्षण विधेयक का अधूरा रहना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक चुनौती है। यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर इस मुद्दे पर सहमति बनाएँ। महिलाओं को संसद निर्गमन और नागरिक समाज में गहरी प्रतिनिधित्व देना भारतीय लोकतंत्र को अधिक सशक्त, न्यायपूर्ण और संतुलित बनाएगा और आज नहीं तो कल यह होकर रहेगा, क्योंकि यही जन आकांक्षा है।



एल.आई.सी

भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।
-भारत सिंह
मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बातों के जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियों, संस्थाएँ या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

आज का राशिफल



मेष: नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। नए विचार दिमाग में आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। धनार्जन होगा। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा।

वृषभ: कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। काम में मन नहीं लगेगा। दूसरे आपसे अधिक की अपेक्षा करेंगे। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। दुःख समाचार प्राप्त हो सकता है। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। क्रोध व उतेजना पर नियंत्रण रखें। पुराना रोग उभर सकता है।

मिथुन: मान-सम्मान मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। आय में वृद्धि होगी। जल्दबाजी न करें। प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी।

कर्क: घर में अतिथियों का आगमन होगा। प्रसन्नता तथा उत्साह बने रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। आलस्य हावी रहेगा। प्रमाद न करें। विवेक का प्रयोग करें। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे।

सिंह: नौकरी में अधिकार वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। निवेश मनोनुकूल रहेगा। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। किसी कार्य के प्रति चिंता रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है।

कन्या: व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। विवाद से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। पुराना रोग उभर सकता है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। किसी भी अपरिचित व्यक्ति की बातों में न आएं। पराक्रम वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।

तुला: व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई बड़ा काम करने की इच्छा जागृत होगी। चिंता तथा तनाव बने रहेंगे। प्रमाद न करें। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे।

वृश्चिक: मान-सम्मान मिलेगा। आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार-व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ होगा। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड इत्यादि से लाभ होगा। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें। थकान रहेगी। किसी कार्य की चिंता रहेगी।

धनु: लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल लाभ देंगे। किसी बड़े काम की रुकावट दूर होगी। **मकर:** कीमती वस्तुएं इधर-उधर हो सकती हैं, संभालकर रखें। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। यात्रा में जल्दबाजी न करें। शारीरिक कष्ट संभव है। पुराना रोग उभर सकता है। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें।

कुंभ: व्यापार व व्यवसाय ठीक चलेगा। नौकरी में चैन रहेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। राजकीय बाधा दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। धनहानि की आशंका है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। थकान व कमजोरी रह सकती है।

मीन: नौकरी में रुतबा बड़ेगा। आय के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं। भाग्योन्नि के प्रयास सफल रहेंगे। जीवन सुखमय व्यतीत होगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं। रोजगार में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। चिंता दूर होगी।

पंच परिवर्तन से समाज में सकारात्मक

बदलाव संभव : वी. सुरेंद्रन

संवाददाता

पश्चिमी सिंहभूम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आयोजित जन गोष्ठी में मुख्य अतिथि एवं भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री वी. सुरेंद्रन ने कहा कि 'पंच परिवर्तन' की अवधारणा के माध्यम से समाज में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्यों के पालन को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बताते हुए युवाओं से इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संघ ने स्थापना काल से ही समाज को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। सेवा, समर्पण और संगठन के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, ग्राम राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। अपने विस्तृत संबोधन में वी. सुरेंद्रन ने

मुंबई में एलपीजी गैस का काला कारोबार बेनकाब, दो जगहों पर छापेमारी

संवाददाता
मुंबई। शहर में एलपीजी गैस के काले बाजार पर रोक लगाने के लिए नागरी आपूर्ति विभाग द्वारा 18 अप्रैल को चलाए गए विशेष अभियान में Domino's Pizza सेंटर में अवैध रूप से एलपीजी गैस के उपयोग का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई में चेंबूर और अनुशक्तीनगर (देवनार) क्षेत्र में दो मामले दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई नियंत्रक शिवावाटप एवं नागरी आपूर्ति विभाग मुंबई के निर्देश पर की गई।
चेंबूर में कार्रवाई: पेस्तमसागर रोड स्थित विश्वसंगम टॉवर के डोमिनोज़ पिज़्ज़ा सेंटर पर छापेमारी के दौरान 8 एलपीजी सिलेंडर बिना बिल के अवैध



रूप से उपयोग में पाए गए। लगभग 25,970 रुपये का माल जब्त किया गया और टिलकनगर पुलिस स्टेशन में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
देवनार में कार्रवाई: अर्जुन सेंटर स्थित डोमिनोज़ पिज़्ज़ा सेंटर पर छापे में 19 एलपीजी सिलेंडर बिना बिल के इस्तेमाल होते पाए गए। करीब 49,117 रुपये का माल जब्त किया गया और गोवंडी पुलिस स्टेशन में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नागरी आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी गैस का अवैध भंडारण और उपयोग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी सख्ती से जारी रहेगी।

शिलफाटा-महापे रोड पर गोदाम में भीषण आग पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

संवाददाता
ठाणे। शिलफाटा-महापे रोड स्थित शिल इलाके में रविवार सुबह एक गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को शिल अग्निशमन केंद्र से सुबह 6:44 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। आग नवाज ढाबा क्षेत्र के शमीम परिसर में स्थित लगभग 4500 वर्ग फुट के गोदाम में लगी थी, जहां हाइड्रोलिक पेपर बेलिंग प्रेस मशीन और बड़ी मात्रा में स्क्रेप कार्डबोर्ड रखा हुआ था। ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही ठाणे नगर निगम के दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही टॉरेंट पावर के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने के लिए दो हार्ड-राइज फायर इंजन, एक रेस्क्यू वाहन और एक जीप तैनात की गई। लगभग पांच



घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने सुबह करीब 11:24 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस आग में गोदाम में रखा स्क्रेप कार्डबोर्ड, हाइड्रोलिक मशीन और बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा है। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अनुसार, आग लगने का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है और मामले की जांच जारी है।

पीएम के भाषण के बाद विपक्ष पर शिंदे का वार



संवाददाता
मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधित किए जाने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी का यह संबोधन विपक्ष के लिए एक बड़ा तमाचा है। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और तुणगूल कांग्रेस जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का असर देश की महिलाओं पर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे घटनाक्रम 21वीं सदी की महिलाएं देख रही हैं और वे समय आने पर इसका उचित जवाब देंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही महिलाओं को उनका अधिकार और सम्मान मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना एनडीए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में आगे रहेगी। विपक्ष पर तीखी टिप्पणीशिंदे ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा

कि यह महिलाओं का अपमान था। उन्होंने कहा कि संसद में इस विधेयक को नामंजूर करना दुर्भाग्यपूर्ण था, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन विपक्ष के लिए करारा जवाब है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकार छीनते समय विपक्ष का खुशी जताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक विधेयक की अस्वीकृति नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान पर हमला है। कांग्रेस की आलोचनादूसरी ओर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाषण प्रचारात्मक था और इसमें कांग्रेस का नाम कई बार लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर सरकार चुनावी व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रही है और संविधान तथा लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

वार्ड क्रमांक 94 में धीमी गति से चल रहा डी-सिल्टिंग का काम

जलजमाव की हो सकती है समस्या

संवाददाता
मुंबई। मुंबई में मानसून से पहले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा हर साल नाले-नालियों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बारिश के दौरान मुंबईकरों को जलजमाव की समस्या से जूझना पड़ता है। वार्ड क्रमांक 94 में नाले-नालियों की सफाई का काम धीमी गति से चल रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। आरोप है कि परिरक्षण विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा डी-सिल्टिंग कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही, सफाई कार्य में लगे मजदूरों की संख्या में भी भारी कमी बताई जा रही है, जिससे काम की रफ्तार प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, जो कामगार नाले-नालियों की सफाई में लगे हैं, उनके कार्य का उचित सुपरविजन भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा शिवालिक वेंचर्स के एसआरए प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले नाले की सफाई अब तक शुरू नहीं हुई है, जिससे आसपास के इलाकों में जलजमाव की संभावना और बढ़ गई है। विशेष रूप से एसआरए इमारत क्रमांक 14 के पीछे स्थित नाले की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है।



स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाले की ओर न तो एसआरए विभाग ध्यान दे रहा है और न ही बीएमसी प्रशासन, जिससे मानसून के दौरान हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या वार्ड

क्रमांक 94 में चल रहे डी-सिल्टिंग कार्यों पर बीएमसी की सहायक आयुक्त मृदुला अंडे समय रहते संज्ञान लेगी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी, ताकि नागरिकों को बारिश के मौसम में राहत मिल सके।

वारिस पठान का अकाउंट हैक, 5 लाख की रंगदारी की मांग

संवाददाता
मुंबई। मुंबई में साइबर अपराध का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एआईएमआईएम (AIMIM) के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान को निशाना बनाया गया है। अज्ञात साइबर अपराधियों ने वारिस पठान का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया है और अब उन्हें ब्लैकमेल करते हुए 5 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की जा रही है। हैकर्स ने पठान को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने फिरौती की रकम नहीं चुकाई, तो उनकी और उनके परिवार की निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ (मॉर्फिंग) कर उन्हें इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस घटना के बाद मुंबई की वल्लो पुलिस और साइबर सेल पूरी तरह सक्रिय हो गई है। वारिस पठान ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें 16 अप्रैल से ही लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज मिलने शुरू हो गए थे। हैकर्स ने अपनी पहचान छिपाने के लिए विदेशी सिम कार्ड्स और इंटरनेट कॉलिंग का सहारा लिया है। पुलिस इस मामले को एक अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट से जोड़कर देख रही है, जो अक्सर सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाकर उनसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक जांच और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस को संदेह है कि वारिस पठान को किए



गए धमकी भरे कॉल कंबोडिया से ओरिजिनेट हुए हैं। हैकर्स ने तीन अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल किया है। साइबर विशेषज्ञों की एक टीम वर्तमान में उन आईपी एड्रेस (IP Address) और डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, जिनका उपयोग अकाउंट हैक करने के लिए किया गया था। कंबोडिया जैसे देशों से संचालित होने वाले ये गिरोह अक्सर 'डिजिटल अरेस्ट' और 'हनी ट्रैप' जैसी वारदातों के लिए कुख्यात हैं। पीड़ित वारिस पठान का आरोप है कि हैकर्स न केवल पैसे मांग रहे हैं, बल्कि उनके परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हैकर्स ने निजी तस्वीरों को अश्लील या आपत्तिजनक रूप में मॉर्फ करने की धमकी दी है, जो किसी भी व्यक्ति की सामाजिक छवि को धूमिल करने का एक खतरनाक हथियार है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वल्लो पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय वसूलने की कोशिश करती हैं। जिनमें जबरन वसूली और धमकी (धारा 308 और 351) शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

लेंसकार्ट पर नया विवाद, निधि मित्तल ने X अकाउंट हटाया

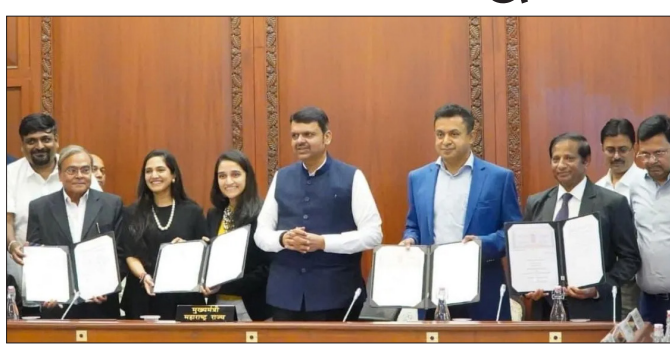
संवाददाता
मुंबई। आईवियर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कर्मचारियों के 'ड्रेस कोड' को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब कंपनी के संस्थापक और CEO पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल बंसल एक नए संकट में घिर गई हैं। निधि मित्तल, जो लेंसकार्ट फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं, ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट (X) डीएक्टिवेट कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब उनके द्वारा 2013 से 2015 के बीच किए गए पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और हिंदू संगठनों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की थीं। इन वायरल स्क्रीनशॉट्स में निधि मित्तल आम आदमी पार्टी (AAP) के समर्थन में 'वोट फॉर मफ्लरमैन' जैसे हैशटैग का उपयोग करती और हिंदू महासभा की आलोचना करती दिखाई दे रही हैं। जैसे ही ये पोस्ट सार्वजनिक हुईं, सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट के खिलाफ 'हिंदू विरोधी' होने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर बहिष्कार (Boycott) की लहर दौड़ गई। आलोचकों का तर्क है कि कंपनी की आंतरिक नीतियों और इसके शीर्ष नेतृत्व की व्यक्तिगत विचारधारा का सीधा संबंध हिंदू प्रतीकों पर लगाई गई पाबंदियों से है। यह नया विवाद ऐसे समय में आया है जब पीयूष बंसल पहले से ही कंपनी की एक 'स्टाइल गाइड' को लेकर स्पष्टीकरण दे रहे थे। फरवरी 2026 की इस गाइडलाइन में कर्मचारियों को बिंदी, तिलक और कलावा पहनने से रोका गया था, जबकि हिजाब और पगड़ी को काले रंग की शर्त के साथ अनुमति दी गई थी। शुरुआती विरोध के बाद पीयूष बंसल ने 15 अप्रैल को एक बयान जारी कर इन दस्तावेजों को पुराना और अनौपचारिक बताया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर 'कम्युनिटी नोट' के जरिए उनकी इस दलील को चुनौती दी गई, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस चूक के लिए माफी मांगी।



23 पन्नों के उस विवादित दस्तावेज़ में ग्रूमिंग नियमों को लेकर कड़े निर्देश थे। इसमें कर्मचारियों से कलाई पर बंधे धार्मिक धागे हटाने और सिंदूर की मात्रा को सीमित रखने की सलाह दी गई थी। हिंदू धार्मिक प्रतीकों के प्रति कंपनी के इस सख्त रवैये और हिजाब के प्रति उदार रुख को सोशल मीडिया पर 'दोहरा मानदंड' करार दिया गया। पीयूष बंसल ने बाद में स्वीकार किया कि बिंदी और तिलक पर रोक वाली बात कभी लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी और इसे आंतरिक रूप से हटाने का दावा किया, लेकिन जनता का गुस्सा अब उनकी पत्नी के पुराने बयानों की ओर मुड़ गया है। निधि मित्तल बंसल न केवल पीयूष बंसल की पत्नी हैं, बल्कि लेंसकार्ट में एक बड़ी शेयरहोल्डर और सामाजिक कार्यों की प्रमुख भी हैं। पत्रकारिता और पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड वाली निधि 'लेंसकार्ट फाउंडेशन' के जरिए अखाओं की जांच और मुफ्त चश्मे बांटने जैसे अभियान चलाती हैं। हालांकि, उनके राजनीतिक विचारों और पुराने ट्वीट्स के सामने आने से अब कंपनी की ब्रांड इमेज को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जानकारों का मानना है कि इस 'डिजिटल फुटप्रिंट' के कारण लेंसकार्ट को भारतीय बाजार में अपनी साख बचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

'मुंबई 3.0' की शुरुआत: रायगढ़ में 216 एकड़ भूमि अधिग्रहण

संवाददाता
मुंबई। मुंबई और नवी मुंबई के बाद अब रायगढ़ जिले में तीसरी मुंबई बसाने के कार्य की शुरुआत हो चुकी है। नवी मुंबई में अंतरराष्ट्रीय अड्डा बनाने के साथ नैना अर्थात् नवीमुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोटिफाई एरिया के रूप में रायगढ़ जिले के पेण इलाके में ग्रोथ सेंटर बनाने के साथ एमएमआरडीए को भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एमएमआरडीए ने अपना काम शुरू कर दिया है। बताया गया कि जन-केंद्रित एवं पारदर्शी भूमि अधिग्रहण नीति को पहले ही दिन उत्साहजनक प्रतिसाद मिला है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। मुंबई 3.0 की महत्वकांक्षी नई शहर संकल्पना के कार्यान्वयन की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने रायगढ़ जिले में प्रस्तावित नए ग्रोथ सेंटर के लिए 216 एकड़ भूमि का भूधारकों को सहमति से एमएमआरडीए की जन-केंद्रित एवं पारदर्शी सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति को मिले उत्साहजनक प्रतिसाद के कारण नीति की घोषणा के पहले ही दिन महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुंबई 3.0 के अंतर्गत प्रस्तावित नए शहर विकास



क्षेत्र में रायगढ़-पेण ग्रोथ सेंटर के लिए भूधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर सहमति मिल रही है। एमएमआरडीए आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी के अनुसार इस सहभागिता की नीति को विश्वास में बदलने का कार्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुआ है। इससे विश्वस्तरीय एकीकृत शहरी विकास परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन को सकारात्मक शुरुआत मिली है। एमएमआरडीए की सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति लागू होते ही भूधारकों ने बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए सहमति प्रदान की है, जिससे अल्प अवधि में बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण संभव हो सका है। विस्थापन नहीं, बल्कि सहमति के माध्यम से विकास के इस मॉडल में भूधारक केवल मुआवजा प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास के दीर्घकालिक भागीदार बन रहे हैं। यह विकास अटल सेतु

(MTHL), नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विचार अलीबाग मल्टी-मोडल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। मुंबई 3.0 का वास्तविक रूप से एमएमआर का नया शहरी इंजन होगा। रायगढ़ ग्रोथ सेंटर को एक बहुआयामी एवं अगली पीढ़ी के शहरी एवं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुआ है। इससे विश्वस्तरीय एकीकृत शहरी विकास परियोजना के वास्तविक क्रियान्वयन को सकारात्मक शुरुआत मिली है। एमएमआरडीए की सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति लागू होते ही भूधारकों ने बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए सहमति प्रदान की है, जिससे अल्प अवधि में बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण संभव हो सका है। विस्थापन नहीं, बल्कि सहमति के माध्यम से विकास के इस मॉडल में भूधारक केवल मुआवजा प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास के दीर्घकालिक भागीदार बन रहे हैं। यह विकास अटल सेतु

को महत्वपूर्ण गति मिलेगी। यह चरण मुंबई 3.0 की संकल्पना को नीति स्तर से आगे बढ़ाकर वास्तविक क्रियान्वयन की दिशा में ले जाने वाला है। सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण मॉडल की पहली बड़ी सफलता से नागरिकों में विश्वास पर आधारित विकास मॉडल की स्वीकार्यता बढ़ने वाली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई 3.0 शहरी विकास का एक नया अध्याय है, जो वास्तव में लोगों के लिए और लोगों की सहभागिता से साकार होगा। इस सहभागितापूर्ण मॉडल के माध्यम से हम केवल भूमि का अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्वास का निर्माण कर रहे हैं। यह समझौता प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले विश्वस्तरीय शहर के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उपमुख्यमंत्री एवं एमएमआरडीए के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई 3.0 केवल एक नया शहर बनाने की परियोजना नहीं है, बल्कि इसे लोगों के साथ मिलकर विकसित करने की पहल है। भूधारकों से मिला सकारात्मक प्रतिसाद इस मॉडल पर बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने कहा कि सहभागितापूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति को मिला प्रतिसाद अत्यंत उत्साहजनक है।

18 KILLED IN FIRECRACKER FACTORY EXPLOSION NEAR VIRUDHUNAGAR

VIRUDHUNAGAR: At least 18 people were killed and several others injured in a powerful explosion at a firecracker manufacturing unit in Kattannarpatti near Virudhunagar on Sunday, sending shockwaves across the region. The incident occurred at the Vanaja Firecracker Factory, owned by Muthu Manickam of Govindanallur, which was reportedly operating with a valid licence. According to officials, around 30 workers were present at the facility when the explosion took place during routine firecracker production. Preliminary reports suggest that friction during the manufacturing process may have triggered the blast, causing highly com-



bustible materials to ignite instantly. The explosion was so intense that at least four rooms of the factory were completely destroyed. Residents in nearby areas reported hearing the sound of the blast from several kilometres away. Fire and rescue services personnel from Sivakasi, Sattur and Virudhunagar rushed to the spot immediately after receiving information. Firefighters battled the flames for over an hour before bringing the blaze under control, paving the way for rescue operations. Rescue teams faced significant chal-

lenges as several workers were trapped under debris. After hours of search operations, authorities confirmed that 18 bodies had been recovered from the site. The injured were shifted to nearby hospitals, where they are undergoing treatment. Superintendent of Police Sreenatha visited the accident site and supervised the rescue efforts. Police have registered a case and launched an investigation to ascertain the exact cause of the explosion and to examine whether safety protocols were followed. The tragedy has once again highlighted concerns over safety standards in firecracker units in the Virudhunagar region, a hub for fireworks manufacturing in Tamil Nadu.

AMIT SHAH VOWS TO PUSH DELIMITATION BILL, TARGETS DMK-CONGRESS AT ERODE RALLY

COIMBATORE: Union Home Minister Amit Shah on Sunday asserted that the NDA government would ensure the passage of the proposed Delimitation Bill in Parliament, accusing the DMK-Congress alliance of blocking efforts to expand political representation in Tamil Nadu. Addressing an election rally in Erode district ahead of the April 23 Assembly polls, Shah said the Centre had proposed increasing the number of Assembly constituencies in the State by 50 per cent to better reflect population changes and strengthen democratic representation. He alleged that the proposal was stalled due to the 'narrow political thinking and vested interests' of the DMK



and Congress. 'We will not accept this conspiracy. The NDA government is committed to fulfilling the aspirations of the people of Tamil Nadu, and I assure you that the Delimitation Bill will be passed,' Shah said. The Union Minister also criticised the opposition over delays in implement-

ing women's reservation in legislatures. Referring to the proposed Women's Reservation Bill, he accused the DMK-Congress alliance of lacking genuine commitment to enhancing women's political participation. Turning to state politics, Shah launched a sharp attack on the DMK leader-

ship, accusing it of promoting dynastic rule. He referred to the political lineage of M. Karunanidhi, his son M. K. Stalin, and the emergence of Udhayanidhi Stalin, alleging that governance had remained concentrated within one family. Pitching for the AIADMK-led NDA alliance, Shah expressed confidence that the coalition would form the next government in Tamil Nadu. He promised that an NDA regime would curb corruption, improve law and order, and restore the State's prominence. The rally was part of Shah's intensive campaign tour as the BJP and its allies seek to expand their footprint in a State traditionally dominated by Dravidian parties.

Punjab Govt's anti-beadbi bill becomes law with Governor's assent : Harpal cheema

CHANDIGARH: The Punjab government, led by Chief Minister Bhagwant Mann, has officially implemented the 'Sri Guru Granth Sahib Satkar Amendment Bill' after receiving assent from the Governor. The legislation mandates life imprisonment for those found guilty of desecration of Sri Guru Granth Sahib. Addressing a press conference at Punjab Bhawan, Cabinet Minister



Harpal Singh Cheema termed the move a decisive step to up-

hold communal harmony and protect the sanctity of religious scriptures. He alleged that incidents of beadbi had occurred during previous regimes, particularly citing the Nakodar incident of 1986 and the Bargari and Behbal Kalan cases of 2015. Cheema criticized earlier governments for failing to deliver justice, stating that multiple commissions and Special Investigation Teams were

formed, but key evidence went missing and investigations remained incomplete. 'Culprits and conspirators were shielded from the law for years,' he said. Highlighting developments since 2022, the minister said the current government has accelerated long-pending investigations. 'For the first time, influential individuals who previously enjoyed political protection have been

compelled to seek anticipatory bail,' he added, reiterating the government's commitment to bring all offenders to justice, regardless of status. Explaining the provisions of the new law, Cheema said it is comprehensive and leaves no room for offenders to escape. It not only targets those directly involved in acts of desecration but also holds masterminds and conspirators accountable. The

legislation also addresses the misuse of 'mental instability' as a defense, making guardians or custodians liable in cases of negligence. Concluding, Cheema said the law fulfills a key promise made by the government and AAP Convenor Arvind Kejriwal. He described it as a strong legal framework aimed at safeguarding religious dignity and maintaining peace in Punjab.

सोशल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराविरोधात निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाईचे दिले निर्देश

नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका आणि आठ मतदारसंघातील पोटनिवडणुकांमध्ये सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की, सर्व संबंधित घटकांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००, आयटी नियम, २०२१ आणि आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदीनुसार डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा जबाबदार आणि नैतिक वापर सुनिश्चित केला पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या मते, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या, कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या किंवा फेरफार केलेल्या मजकुरावर तीन तासांच्या आत कारवाई करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रचार प्रतिनिधींनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे



की, कोणताही कृत्रिमरित्या तयार केलेला किंवा बदललेला मजकूर 'कृत्रिमरित्या तयार केलेला' किंवा 'डिजिटली सुधारित' म्हणून स्पष्टपणे चिन्हांकित केला जाईल आणि त्याचा स्रोत उघड केला जाईल. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि पश्चिम बंगालमध्ये सुरु असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियावरील मजकुरावर लक्ष ठेवले जात असल्याचे आयोगाने

म्हटले आहे. आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या, कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या किंवा मतदान प्रक्रियेवद्दल दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्या मजकुरावर संबंधित अधिकारी कारवाई करत आहेत. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, १५ मार्च रोजी निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून, ११,००० हून अधिक आक्षेपाई सोशल मीडिया पोस्ट आणि यूआरएल (URLs) ओळखण्यात

आले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये मजकूर हटवणे, एफआयआर दाखल करणे, स्पटीकरण मागवणे आणि खंडन करणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम १२६ च्या तरतुदींचा पुनरुच्चार केला आहे, ज्यात म्हटले आहे की मतदान संपण्यापूर्वीच्या ४८ तासांच्या शांतता कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक प्रचारास मनाई असेल आणि सर्व माध्यमांनी याचे कोटकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. आयोगाने म्हटले आहे की नागरिक, राजकीय पक्ष आणि उमेदवार 'सी-व्हिजिल' (C-Vigil) प्लॅटफॉर्मद्वारे आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या तक्रारी दाखल करू शकतात. १५ मार्च ते १९ एप्रिल दरम्यान या माध्यमातून ३,२३,०९९ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, त्यापैकी ९६ टक्के तक्रारी १०० मिनिटांच्या निधारित वेळेत सोडवण्यात आल्या.

कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई करत कोलकाता पोलिसांचे पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) शान्तू सिन्हा बिस्वास यांच्या निवासस्थानी छाप टाकली आहे. ईडीची टीम रविवारी सकाळी सुमारे ७ वाजता बालीगंज येथील फर्न रोडवरील त्यांच्या घरी पोहोचली आणि झडती मोहीम सुरु केली. माहितीनुसार, डीसीपी बिस्वास यापूर्वी कालीघाट पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी होते, जे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघात येते. याचदरम्यान, ईडीने दक्षिण कोलकात्यातील बेहाला भागात व्यापारी जांय कामदार यांच्या घरावरही छाप टाकली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या व्यापार्याच्या घरातून यापूर्वीही रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती आणि तपास यंत्रणेने त्यांना चौकशीसाठी दोन वेळा समनस पाठवले होते, मात्र ते



हजर झाले नव्हते. ही कारवाई अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा राज्याच्या राजधानीत अवैध बांधकाम किंवा सिंडिकेट प्रकरणात शुरुवाती अनेक ठिकाणी झडती घेण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वीच ईडीने माजी राज्यमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणातही त्यांच्या निवासस्थानी छाप टाकली होती. याशिवाय, आयकर विभागाने नुकतेच बहिरा येथील आमदार आणि तुणमूल काँग्रेसचे उमेदवार देबाशीष कुमार यांच्या घरावरही छाप टाकली होती.

उल्लेखनीय म्हणजे, २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तुणमूल काँग्रेसने २१३ जागांसह दणदणीत विजय मिळवला होता. भारतीय जनता पक्षाने ७७ जागांसह मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळवले होते. आगामी निवडणुकीत दोन्ही पक्षांमध्ये कडवी लढत होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक राज्याच्या राजकीय दिशेला आकार देणारी ठरणार आहे. पश्चिम बंगालमधील २९४ जागांसाठी २३ आणि २९ एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत मतदान होणार असून, ४ मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत.

इराण-अमेरिका शांतता चर्चेत प्रगती, पण अंतिम करार अजून दूर- मोहम्मद गलिबाफ

तेहरान: इराण आणि अमेरिका यांच्यात दुसऱ्या टप्प्यातील शांतता चर्चेची लवकरच शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, इराणने सांगितले की अमेरिकेसोबतच्या शांतता चर्चेत काही प्रगती झाली आहे, मात्र अंतिम करार अद्याप खूप दूर आहे. कारण दोन आठवड्यांचा युद्धविराम बुधवारी संपणार आहे. इराणी संसदेचे सभापती मोहम्मद बाघेर गलिबाफ यांनी शनिवारी दूरदर्शनवरील संबोधनात सांगितले की, अजूनही अनेक उणिवा आहेत आणि काही मूलभूत मुद्दे प्रलंबित आहेत. गलिबाफ म्हणाले, 'आपण अजूनही अंतिम चर्चेपासून खूप दूर आहोत.' गत शनिवारी पाकिस्तानमध्ये

झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील चर्चेत इराणी शिष्टमंडळाचे नेतृत्वही गलिबाफ यांनीच केले होते. त्यांनी असेही सांगितले की, अनेक आठवडे चाललेल्या युद्धात इराण रणांगणावर विजयी राहिला आणि वॉशिंग्टनसोबत केवळ आपल्या मागण्या मान्य झाल्यामुळेच तालुकरा युद्धविरामास सहमती दिली. अमेरिकेचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, 'आम्ही युद्धविराम स्वीकारला, कारण त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या.' गलिबाफ यांनी दावा केला की अमेरिका आपले उद्दिष्ट साध्य करू शकली नाही आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या होमुंज सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण कायम आहे.ते पुढे म्हणाले की, शत्रूचा



प्रत्येक प्रयत्न आमच्यावर त्याच्या मागण्या लादण्याचा होता. त्यामुळे आपल्या हक्कांची नोंद करून देणे आवश्यक आहे आणि म्हणूनच येथे चर्चा हा संघर्षाचाच एक मार्ग आहे. त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर

निशाणा साधत म्हटले की, इराणमध्ये सत्तांतर घडवून आणणे आणि त्याची लष्करी क्षमता संपवणे हे ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट पूर्णपणे अपयशी ठरले. गलिबाफ यांनी असेही म्हटले की, 'इराण हा व्हेनेझुएला नाही,' म्हणजेच बाहेरील दबावामुळे येथे सरकार बदलता येणार नाही. इराणी संसदेच्या अध्यक्षांनी मान्य केले की लष्करी ताकदीच्या बाबतीत अमेरिका इराणपेक्षा अधिक बलवान आहे. मात्र त्यांनी टामपणे सांगितले की, केवळ शस्त्रे, पैसा आणि संसाधने यावर विजय ठरत नाही. त्यांच्या मते, इराणने 'असिमेट्रिक वॉरफेअर' म्हणजेच वेगळी रणनीती अवलंबून शक्तिशाली शत्रूला मागे हटवले. दरम्यान, अमेरिका

आणि इराण यांच्यातील चर्चेबाबत त्यांनी सांगितले की, काही मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे, पण अजूनही अनेक मोठे मतभेद कायम आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, इराण आपल्या राष्ट्रीय हितांशी कोणतीही तडजोड करणार नाही आणि कूटनीतीत झुकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मोहम्मद गलिबाफ यांनी असा आरोपही केला की, अमेरिका 'अमेरिका फर्स्ट'ची भाषा करते, पण प्रत्यक्षात ती इस्त्रायलच्या हितांना प्राधान्य देते आणि त्याच आधारावर निर्णय घेते. तथापि, प्रत्यक्ष परिस्थिती अजूनही तणावपूर्णच आहे. अलीकडील घडामोडींमध्ये होमुंज सामुद्रधुनीबाबत वारंवार भूमिका बदलताना दिसत आहे. कधी ती खुली

करण्याची घोषणा केली जाते, तर कधी पुन्हा बंद करण्याची चर्चा समोर येत आहे. गलिबाफ आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने ११ एप्रिल रोजी इस्लामाबाद येथे अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्यासोबत बंद दाराआड चर्चा केली होती. १९७९ च्या इस्लामी क्रांतीनंतर इराण आणि अमेरिका यांच्यात झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात उच्चस्तरीय संपर्क मानला जात आहे. मात्र, या चर्चेत कोणताही अंतिम करार होऊ शकला नाही. इराणचे उपपराष्ट्र मंत्री सईद खतीबजादेह यांनी सांगितले की, अमेरिकेसोबतच्या पुढील चर्चेच्या फेरीसाठी अद्याप कोणतीही तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.

ईशा और अविनाश का नया गाना 'शुक्रिया' रिलीज हुआ

मुंबई। 'विग बॉस 18' की मशहूर दोस्ती ईशा और अविनाश ने हमेशा फैंस को आकर्षित किया है। 'विग बॉस' के बाद अक्सर इनके रिश्ते की खबरें भी आती रहीं, लेकिन दोनों ने बार-बार साफ कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब दोनों ने मिलकर फैंस के लिए एक खास तोहफा पेश किया है। दोनों का शुक्रवार को नया गाना 'शुक्रिया' रिलीज हो गया। इस गाने में ईशा और अविनाश की लव स्टोरी भी देखने को मिल रही है। इसमें हल्दी, फेरे और शादी की सुंदर रस्में दिखाई गई हैं। यह गाना बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक है। प्ले डीएमएफ के अंशुल गर्ग द्वारा प्रोड्यूस किए



गए इस गाने को हंसिका पारिक और विभोर पराशर ने अपनी शानदार आवाज में गाया है। गाने का म्यूजिक रजत नागपाल ने तैयार किया है। इस गाने पर अंशुल ने कहा, 'अविनाश और ईशा को उनके फैंस से बेहतरीन प्यार मिलता है, वह कमाल का है। फैंस के लिए यह गाना बनाना हमारे लिए

गर्व की बात है। दोनों ही बेहद टैलेंटेड एक्टर हैं और रोमांस करना उनके लिए बिल्कुल नेचुरल है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक 'शुक्रिया' को भी उतना ही प्यार देंगे, जितना उन्होंने इन दोनों को दिया है।' अविनाश ने ईशा के साथ दोबारा काम करने को लेकर कहा, 'हमारे फैंस काफी समय से

कह रहे थे कि हम एक साथ कुछ प्रोजेक्ट करें। इसी कारण 'शुक्रिया' उनके लिए हमारा खास तोहफा है। ईशा के साथ स्क्रीन शेयर करते समय पुगनी यादें ताजा हो गईं। यह खूबसूरत गाना इस अनुभव को और यादगार बना देता है।' वहीं, ईशा ने भी अपनी बात को रखते हुए कहा, 'फैंस में हमारे एक साथ आने को लेकर जो दीवानगी थी, उसी वजह से हमने इस गाने के लिए हॉट कंटाई। यह गाना इतना दिल को छूने वाला और भावुक है कि इसे दुकराना नामुमकिन था। दर्शकों से हमें जितना प्यार मिला है, मुझे उम्मीद है कि 'शुक्रिया' को भी उतना ही प्यार मिलेगा।'

रणवीर-दीपिका फिर बनने वाले हैं माता-पिता

मुंबई। 'धुरंधर: द रिवेज' की सक्सेस का स्वाद चख रहे रणवीर सिंह की खुशी और अधिक बढ़ चुकी है क्योंकि वे दोबारा पिता बनने वाले हैं। खुद दीपिका पादुकोण ने अपनी सेकेड प्रेग्नेसी की न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की है। खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हर कोई कपल को दिल खोलकर बधाई रहे हैं। अभिनेत्री ने बड़े ही यूनिक स्टाइल में प्रेग्नेसी की खबर शेयर की है। दीपिका पादुकोण ने 8 सितंबर 2024 को पहली बेटी दुआ को जन्म दिया था लेकिन अब 19 महीने बाद दूसरी प्रेग्नेसी की अनाउंसमेंट कर दी है। दीपिका ने सोशल मीडिया पर दुआ की फोटो शेयर की है और दुआ के साथ में प्रेग्नेसी किट है, जिसपर दो लाइन हैं, जो प्रेग्नेसी को कंफर्म करती हैं। अभिनेत्री ने फोटो के साथ कैप्शन में इविल आई का



स्टीकर लगाया है। फोटो में दुआ का चेहरा भी आधा दिख रहा है। प्रेग्नेसी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाई का ताता लग गया है। बॉलीवुड सेलेब्स और अभिनेत्री को चाहने वाले उन्हें दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं। अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु ने ढेर सारे दिल कमेंट में पोस्ट किए हैं, जबकि यश देसाई ने दुआ को बड़ी बहन बनने की बधाई दी है। बता दें कि दीपिका पादुकोण ने 8

सितंबर 2024 को पहली बेटी दुआ को जन्म दिया था और उनकी पहली झलक दीपावली के मौके पर दिखाई थी। दीपिका ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी प्रेग्नेसी जर्नी काफी मुश्किल रही थी क्योंकि उनका सातवां और आठवां महीना काफी दर्द में बीता था। बेटी के जन्म के बाद से दीपिका पूरा ध्यान अपने परिवार पर दे रही हैं, लेकिन वे आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट्स में दिखने वाली हैं। अभिनेत्री शाहरुख खान की 'किंग' और 'पठान-2' में दिखेंगी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण निर्देशक एटली और अभिनेता अल्लू अर्जुन की आगामी 'राका' में भी नजर आने वाली हैं। फिल्म से अभिनेता अल्लू अर्जुन का पहला लुक भी सामने आ चुका है। फिल्म सक्सेस और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है।

'पति पत्नी और वो 2' की रिलीज डेट घोषित



मुंबई। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। शनिवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। आयुष्मान खुराना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया। इसमें

अभिनेता जाल में फंसे दिख रहे हैं, जबकि चीता बाहर है। पोस्टर शेयर कर आयुष्मान ने लिखा, 'शिकारी खुद हो गया शिकार। अब जाल में फंस गए हमारे प्रजापति पांडे। हो जाओ 'पति पत्नी और वो दो' के लिए तैयार, क्योंकि यह 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।' यह फिल्म एक मजेदार रिलेशनशिप कॉमेडी-ड्रामा फिल्म

है, जिसमें आयुष्मान और सारा अली खान के साथ चामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं। मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है जो प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मूवी आपको प्रजापति पांडे की दुनिया में लेकर जाएगी। इस कहानी में आपको ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस का तड़का देखने को

मिलेगा। इस फिल्म को भूषण कुमार और रेणु रवि चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है। इस फिल्म ने उस समय बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसे देखते हुए फिल्म को फिर से नई कहानी और किरदारों के साथ रिलीज किया जाएगा। देखा होगा कि

दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देते हैं। 'पति पत्नी और वो' में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर, और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे, जो कानपुर के एक इंजीनियर चिटू त्यागी के विवाहबंध संबंध और उसके बाद की कॉमेडी को दर्शाती है। यह एक हल्की-फुल्की फिल्म है जो वैवाहिक जीवन की जटिलताओं को दिखाती है।

दिल को स्वस्थ रखने के लिए तनाव पर नियंत्रण जरूरी

आधुनिक जीवनशैली में काम का बोझ, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता ने तनाव को हर घर का हिस्सा बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आप महज एक मानसिक स्थिति समझ रहे हैं वह आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जानकारी के अनुसार लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव हृदय रोगों के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो सीधे तौर पर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। यदि इसे समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियों का कारण बन सकता है।

गहरी सांस

तनाव को तुरंत कम करने का सबसे सरल तरीका है गहरी सांस लेना। आयुर्वेद में इसे प्राणायाम का आधार माना गया है। जब आप धीरे-धीरे गहरी सांस लेते हैं और उसे धीरे ही छोड़ते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। विज्ञान कहता है कि यह प्रक्रिया हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम



को सक्रिय करती है जिससे दिल की धड़कन सामान्य होती है और मन को तत्काल शांति मिलती है।

शारीरिक सक्रियता

रोजाना केवल 30 मिनट की वॉक या योगासन आपके मूड को बेहतर बनाने वाले एंडोफिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्यायाम शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है जबकि आधुनिक विज्ञान मानता है कि नियमित एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर

होता है और हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

साल्विक आहार

आयुर्वेद में साल्विक भोजन को सर्वोत्तम माना गया है। ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी न केवल शरीर को पोषण देते हैं बल्कि मन को भी स्थिर रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट शरीर की सृजन को कम करती है जो हृदय रोगों का एक मुख्य कारण है।

ब्यूटी स्लीप

नींद की कमी सीधे तौर पर तनाव हार्मोन को बढ़ाती है। जब आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हैं तो शरीर खुद को रिपेयर करता है और हृदय पर पड़ने वाला अनावश्यक दबाव कम हो जाता है। अच्छी नींद न केवल आपके दिमाग को तरोताजा करती है बल्कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद करती है।

मेडिटेशन

नियमित ध्यान या मेडिटेशन तनाव के स्तर को स्थायी रूप से कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह न केवल मानसिक स्पष्टता देता है बल्कि हृदय की कार्यप्रणाली में भी सुधार करता है। प्रतिदिन केवल 10-15 मिनट का मौन आपके दिल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। दिल की सेहत केवल जिम जाने या डाइट करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। अपनी जीवनशैली में इन छोटे बदलावों को शामिल कर आप एक लंबे और स्वस्थ जीवन की नींव रख सकते हैं।

होंठों का कालापन दूर करें चुकंदर के इस घरेलू नुस्खे से

खूबसूरत और गुलाबी होंठ चेहरे की रौनक बढ़ा देते हैं लेकिन प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल के कारण होंठों का कालापन एक आम समस्या बन गई है। बाजार में मिलने वाले लिप बाम अक्सर केमिकल से भरे होते हैं। ऐसे में चुकंदर लिप बाम एक जादुई घरेलू नुस्खा है जो आपके होंठों को नेचुरल गुलाबी रंगत देने के साथ-साथ उन्हें गहराई से मॉइस्चराइज भी करता है। चुकंदर में प्राकृतिक रूप से गहरे लाल और गुलाबी रंग के तत्व पाए जाते हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के होंठों की रंगत सुधारने में मदद करते हैं। यह न केवल होंठों के कालापन को दूर करता है बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को पोषण भी देते हैं। इसके लिए आप घर पर नेचुरल लिप बाम बना सकते हैं जो होंठों के लिए सही साबित होगा।

आवश्यक सामग्री

- चुकंदर: 1 मध्यम आकार का (कहूकस किया हुआ)
- नारियल तेल या बादाम तेल: 1 बड़ा चम्मच
- शहद: आधा छोटा चम्मच (नेचुरल चमक के लिए)
- विटामिन-E कैप्सूल: 1 (लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए)
- वैसलीन या शिशा बटर (वैकल्पिक): गाढ़ापन देने के लिए

बनाने की विधि

- सबसे पहले चुकंदर को कहूकस करके उसका सारा रस एक सूती कपड़े या छलनी की मदद से निकाल लें।
- इस रस को एक धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा और आधा न रह जाए। (आप कच्चे रस का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पका हुआ रस ज्यादा समय तक चलता है।)
- अब एक कटोरी में चुकंदर का रस, नारियल तेल, शहद और विटामिन-E का लिक्विड अच्छी तरह मिला लें।
- इस मिश्रण को एक छोटी साफ डिब्बी में भर लें।
- इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में जमाने दें। आपका नेचुरल पिंक लिप बाम तैयार है।
- इस्तेमाल करने के फायदे
- इसे लगाने के बाद आपको भारी लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह एक नेचुरल 'टिंट' का काम करता है।
- नारियल तेल और शहद होंठों की दरारों को भरते हैं और उन्हें मखमली कोमल बनाते हैं।
- यह पूरी तरह से केमिकल फ्री है और किचन की चीजों से तैयार हो जाता है।
- बेहतर रिजल्ट के लिए रात को सोने से पहले इसे लगाएं। सुबह तक आपके होंठ नरम और गुलाबी नजर आएंगे।

कैरियर लिटरेचर: सफलता का मार्गदर्शन या सिर्फ मोटिवेशन?

कैरियर लिटरेचर यानी कैरियर के लिए प्रोत्साहित करने वाली किताबें, लेख, ब्लॉग, बायोग्राफी गाइड्स आदि का क्या वास्तव में हमारी कैरियर ग्रोथ में कोई रोल होता है या फिर यह एक मनोविज्ञान भर है? इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। मगर हकीकत ये है कि कैरियर लिटरेचर न तो कोई चमत्कार है कि उसे पढ़ते ही आपका कैरियर चमक जायेगा और न ही कोरा भ्रम है कि उससे कुछ होगा ही नहीं। वास्तव में कैरियर लिटरेचर हमारे प्रोफेशनल जीवन में कई तरह की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, अगर हम उसकी इन भूमिकाओं के महत्व को समझ लें, तो जान सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जानिये आखिर किसी नौकरी चाहने वाले व्यक्ति के जीवन में कैरियर लिटरेचर का क्या महत्व होता है?

निर्णायक दिशा देता है

ईमानदारी से मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उनमें हरेक के पास अपने कैरियर को लेकर कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। कैरियर लिटरेचर हमें यह दिशा देने की कोशिश करता है। कैरियर लिटरेचर के जरिये हम

इस बात को समझते हैं कि अपने मौजूदा दौर के मुताबिक वह कौन सी स्किल हो सकती है, जो हमारे कैरियर को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए या इन दिनों किस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कैरियर का कौन का गुरु मंत्र होना जरूरी होता है। विशेषकर आपकी इच्छित इंडस्ट्री के संदर्भ में। कैरियर लिटरेचर से हमें यह भी पता चलता है कि कोई शाख आखिर किस-किस तरह की गलतियां कर सकता है और इन गलतियों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इस तरह देखें तो कैरियर लिटरेचर हमें न केवल दिशा देता है बल्कि हमारी सोच बदलता है और हमारे कई तरह के भ्रमों को भी खत्म करता है। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि कैरियर लिटरेचर महज एक भ्रम है। कैरियर लिटरेचर की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वह हमारे माइंड सेट यानी हमारी सोच को बदल सकता है। 'मैं ऐसा नहीं कर सकता' से वह हमें 'इसे सीखकर मैं भी कर सकता हूँ' के माइंड सेट तक ले जाता है। यह बदलाव साधारण नहीं है। बदलाव की इस सोच की बदौलत हम असफलता से बच



जाते हैं, तो कहना ये चाहिए कि कैरियर लिटरेचर सिर्फ हमें जानकारी नहीं देता, हमारी सोच की ट्रेनिंग भी करता है।

इससे हमारा व्यवहार बदलता है

कैरियर लिटरेचर इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह हमें छोटे-छोटे एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। मसलन, रोज एक घंटा स्किल सीखना एक ऐसी प्रेरणा है कि अगर हम इसे एक महीने तक बरकरार रख पाएं, तो वास्तव में हम किसी स्किल को अच्छी तरह से सीख लेते हैं। वहीं कैरियर लिटरेचर ही हमें नेटवर्किंग शुरू करने की

काबिलियत देता है और हमारा रिज्यूमे किस तरह अट्रैक्टिव या आकर्षक बने, इसकी भी समझ कैरियर लिटरेचर से ही आती है। इन सभी चीजों का सचमुच हमारे कैरियर ग्रोथ से लेना-देना होता है। क्योंकि कैरियर में बदलाव सचमुच यहीं से आता है। इसलिए यह मान लेना सच नहीं होगा कि कैरियर सिर्फ एक साइकोलॉजी है। यह बात सही है कि मनोविज्ञान इसमें बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन यह सिर्फ साइकोलॉजी भर नहीं होता। कैरियर लिटरेचर हमारे कैरियर में कई जगह महत्वपूर्ण होता है, जहां हम इस संबंध में इससे पढ़े गये विचारों और सीखों को सचमुच की अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। क्योंकि कैरियर लिटरेचर का कंटेंट व्यावहारिक और वास्तविक होता है। यह अनुभवों के निष्कर्ष के जरिये सामने आता है। लेकिन यह भी सही है कि केवल पढ़कर लेने से हम कैरियर में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि इंस्टैंट सक्सेस वाली जितनी बातें कैरियर लिटरेचर में पढ़ने को मिलती हैं, वो उसी तरह व्यवहारिक जीवन में खरी नहीं उतरती। यही कारण है कि बार-बार मोटीवेशन लेकर भी कई बार हमारी आदतें

बदलने का नाम नहीं लेतीं। कुल मिलाकर कहना चाहिए कि कैरियर लिटरेचर में 30 फीसदी तो मोटीवेशन होता है और 70 प्रतिशत एक्शन का ब्लू प्रिंट होता है। अगर कैरियर लिटरेचर में एक्शन ब्लू प्रिंट नहीं है, तो वह सिर्फ डोपामाइन डोज बनकर रह जाता है।

मोटीवेशनल वीडियोज के क्रेज में कमी की वजह

हाल के कुछ सालों में यह ट्रेड देखने को मिला है कि मोटीवेशनल वीडियोज को लेकर अब लोग वैसे पागल नहीं हैं, जैसे एक जमाने में हुआ करते थे। क्योंकि लोगों ने अब व्यावहारिक रूप से यह समझ लिया है कि अच्छी-अच्छी बातें सुनकर हम अच्छे नहीं हो जाते, जब तक कि अच्छा बनने के लिए हाइ टोड मेहनत न करें। अक्सर बार-बार मोटीवेशनल वीडियोज सुनने से एक ही चीज रिपीट होती रहती है और इस रिपीटेशन के ओवरडोज से हम पर उसके प्रभाव या विश्वास का जादू कम हो जाता है, क्योंकि बार-बार एक ही चीज पढ़ने, सुनने से हम सीखते कम हैं, बस उन्हें सुनने तक सीमित रखते हैं। यही कारण है कि कुछ जुमले जो

साधारण तौरपर प्रभावित करने वाले होते हैं और वो बार-बार दोहराए जाने के कारण मजाक बनकर रह जाते हैं और उनका प्रभाव सिर्फ सुनने तक रहता है। उन पर अमल करना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि इसके लिए हम उत्साहित भी नहीं हो पाते। जैसे जब हम दिन-रात इस तरह मुहावरे सुनते हैं- 'नेवर गिवअप', 'यू कैन डू इट' को बार-बार सुनकर उनकी वैल्यू हममें नहीं रह जाती, सिर्फ दोहराए रह जाता है। कई बार इस तरह के वीडियोज का प्रभाव तब एक झटके में कम या खत्म हो जाता है, जब हम असल जिंदगी की कठिनाइयां देखते हैं और कैरियर लिटरेचर में यह सब बड़ी आसानी से होता देखते हैं। इस अंतर को महसूस करने के बाद हम एक अजीब तरह की निराशा या डिप्ल्यूज में घिर जाते हैं। इस तरह कैरियर लिटरेचर हमें प्रोत्साहित तो करता है, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है, न कोई जादू कि सब कुछ एक झटके में हो जाए। यह तभी काम करता है, जब हम इससे सिर्फ प्रभावित नहीं होते बल्कि उस प्रभाव में सामान्य से कई गुना ज्यादा मेहनत करने का मादद रखते हैं।

भोजला मंडी में गेहूं खरीद का औचक निरीक्षण व्यवस्थाओं को परखने पहुंचे एडीएम वरुण कुमार पांडेय

संवाददाता
झांसी, उत्तर प्रदेश। भोजला मंडी में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत चल रही गेहूं खरीद का जायजा लेने के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं जिला खरीद अधिकारी वरुण कुमार पांडेय ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य विभाग के दो तथा भारतीय खाद्य निगम के एक राजकीय गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने केंद्र प्रभारियों से अब तक हुई गेहूं खरीद की जानकारी ली और निर्देश दिए कि क्षेत्र में सक्रिय रूप से भ्रमण कर अधिक से अधिक किसानों से उनकी फसल की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी किसान को केंद्र से वापस नहीं लौटाया जाए और सभी को प्राथमिकता के साथ सुविधा दी जाए। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए सभी क्रय केंद्रों पर लेखापाल एवं जनसेवा केंद्र संचालकों



की ड्यूटी लगाई गई है, जो मौके पर ही फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे, जिससे अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। एडीएम वरुण कुमार

पांडेय ने अब तक हुई 13,455 मीट्रिक टन गेहूं खरीद पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन खरीद को और बढ़ाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों के अभिलेखों की जांच की

और समय से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि किसानों को भुगतान आधार लिंक बँक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से 72 घंटे के भीतर किया जाए।

उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग बंद मरम्मत कार्य के चलते यातायात डायवर्ट, आमजन को हो रही परेशानी

भूपेंद्र सिंह
उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उन्नाव नगर में स्थित लखनऊ रोड रेलवे क्रॉसिंग को रेलवे विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को बंद कर दिया गया। यहाँ ट्रैक पर टैपिंग और ओवरहालिंग का कार्य शुरू किया गया है,



जो रविवार तक जारी रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कार्य रेल ट्रैक की मजबूती और सुरक्षित संचालन के लिए किया जा रहा है। हालांकि, क्रॉसिंग बंद होने के कारण आम नागरिकों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है। लखनऊ से बांगरमऊ की ओर आने वाले हल्के वाहनों को ग्राम सुरसेनी के सामने से गौरा होते हुए संडीला मार्ग की ओर डायवर्ट किया गया है। वहीं चौपहिया और दोपहिया वाहन सवारों

को ग्राम मऊ होकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की सलाह दी गई है। मार्ग परिवर्तन के चलते कई स्थानों पर जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त समय लग रहा है। रेलवे विभाग ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कार्य जनहित में कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में रेल सेवाएं अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकें। विभाग ने आश्वासन दिया है कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही सोमवार को रेलवे क्रॉसिंग को पुनः खोल दिया जाएगा और आवागमन सामान्य रूप से बहाल कर दिया जाएगा।

महिला आरक्षण बिल को लेकर मोहन यादव ने विपक्ष पर साधा निशाना, प्रदेशभर में आंदोलन का ऐलान

संवाददाता
भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में हुए घटनाक्रम को 'निंदनीय और कष्टकारी' बताया। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर में आंदोलन और "नारी शक्ति वंदन पदयात्रा" निकालने की घोषणा की है। वे आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार-वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र इस समय एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है और संसद में जो घटनाक्रम देखने को मिला, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भावुक टिप्पणी करते हुए कहा, "द्वैपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन आज संसद में बहनों की इज्जत के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, वह अत्यंत पीड़ादायक है।" उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर शुरुआत से ही सभी दलों को सुझाव देने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी दलों को खुला पत्र लिखकर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, ताकि किसी को यह शिकायत न रहे कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। इसके बावजूद विपक्ष के रवैये को उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना बताया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूषिया, प्रदेश शासन की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, पार्टी की प्रदेश



प्रवक्ता व विधायक अर्चना चिटनीस, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया एवं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर अब भाजपा सरकार और संगठन जनता के बीच जाएगा। सोमवार से "नारी शक्ति वंदन पदयात्रा" शुरू की जाएगी, जोकि पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से निकलेगी। इसके तहत सभी जिलों में प्रदर्शन होंगे और स्थानीय निकायों नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि इस मुद्दे पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें विस्तृत चर्चा और निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है और राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस मुद्दे को उलझा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में जिस अधिनियम को सभी दलों ने समर्थन दिया था, अब उसी पर विपक्ष का रुख बदल गया है। "जब चुनाव नजदीक थे, तब समर्थन किया गया और अब जब समय है तो विरोध किया जा रहा है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है।" उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसने पहले ही महिलाओं से जुड़े अश्विनी परांजपे और मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर अब भाजपा सरकार और संगठन जनता के बीच जाएगा। सोमवार से "नारी शक्ति वंदन पदयात्रा" शुरू की जाएगी, जोकि पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से निकलेगी। इसके तहत सभी जिलों में प्रदर्शन होंगे और स्थानीय निकायों नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि इस मुद्दे पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें विस्तृत चर्चा और निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है और राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस मुद्दे को उलझा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में जिस अधिनियम को सभी दलों ने समर्थन दिया था, अब उसी पर विपक्ष का रुख बदल गया है। "जब चुनाव नजदीक थे, तब समर्थन किया गया और अब जब समय है तो विरोध किया जा रहा है।

उन्नाव में स्मार्ट मीटर बना सिरदर्द: उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

संवाददाता
उन्नाव, उत्तर प्रदेश। उन्नाव जनपद में लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर अब आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। अत्यधिक बिलिंग, बिना सूचना बिजली कटौती और सर्वर फेल्योर जैसी समस्याओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते नर सेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव ने सैकड़ों पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के संस्थापक और प्रखर हिंदू नेता विमल द्विवेदी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल दो से तीन



गुना तक बढ़ गया है, जबकि घरेलू खपत पहले जैसी ही है। सबसे बड़ी समस्या प्रीपेड बैलेंस खत्म होने पर हो रही है। आरोप है कि बिजली विभाग बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बिजली काट देता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की देखभाल तक प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, रिचार्ज करने के बाद भी सर्वर की खराबी के चलते कई घंटों तक बैलेंस

अपडेट नहीं होता और उपभोक्ताओं को अंधेरे में बैठना पड़ता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि मीटर की रिडिंग और बैलेंस कटौती की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम आदमी के समझ से बाहर है, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं और उपभोक्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। समिति ने अपनी तीन प्रमुख मांगों भी रखीं—मीटरों की तकनीकी जांच

के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन, रिचार्ज खत्म होने से कम से कम 24 घंटे पहले कॉल या एसएमएस के जरिए सूचना देना अनिवार्य किया जाए, और जिला स्तर पर तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन डेस्क स्थापित की जाए। समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन सुझावों पर अमल संभव नहीं है, तो जनहित में स्मार्ट मीटर व्यवस्था को हटाकर पुरानी मीटर प्रणाली बहाल की जाए, ताकि आम जनता को तत्काल राहत मिल सके। ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार जहां 'ईज ऑफ लिविंग' की बात करती है, वहीं स्मार्ट मीटर ने आम आदमी का जीवन मुश्किल बना दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी और उपभोक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की।

छत्तीसगढ़ के सक्ति वेदांता प्लांट हादसे में अब तक 24 की मौत

संवाददाता
सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे में हुए मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। आज रविवार सुबह रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक और गंभीर रूप से घायल मजदूर ने दम तोड़ दिया। 14 अप्रैल को हुए इस दर्दनाक हादसे में कुल 36 मजदूर झुलसे थे, जिनमें से अब 12 का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में जारी है। सक्ती जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि वेदांता पावर प्लांट हादसे में गंभीर रूप से घायल मनीष कुमार ने उपचार के दौरान आज दम तोड़ दिया। रायगढ़ स्थित लखीराम मेडिकल कॉलेज में



भर्ती झारखंड के रहने वाले मनीष कुमार की मौत के साथ हादसे में मृत श्रमिकों की संख्या 24 पहुंच गई है। वहीं अन्य घायल श्रमिकों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उल्लेखनीय है कि घटना के बाद से ही अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि वेदांता पावर प्लांट हादसे में गंभीर रूप से घायल मनीष कुमार ने उपचार के दौरान आज दम तोड़ दिया। रायगढ़ स्थित लखीराम मेडिकल कॉलेज में

करते हुए वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित 10 लोगों के खिलाफ डभरा थाने में एफआईआर दर्ज की है। इस कार्रवाई को लेकर देश के जाने-माने उद्योगपति नवीन जिंदल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना पूरी जांच के किसी बड़े उद्योगपति का नाम एफआईआर में शामिल करना चिंता का विषय है। उनका कहना है कि पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ठोस सबूतों के आधार पर ही जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। हादसे की जांच में अब प्लांट के संचालन और मटेनेंस की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी

एनजीएसएल की भूमिका भी अहम हो गई है। एनजीएसएल, एनटीपीसी और जीई पावर इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें दोनों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी बताई जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हादसे के पीछे तकनीकी खामी थी या मानवीय लापरवाही। इधर, हादसे के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। वहीं घायल मजदूरों के बेहतर इलाज के लिए प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मां गंगा के जयकारों के बीच खुले गंगोत्री मंदिर के कपाट संसद में महिला आरक्षण संबंधी बिल गिराकर सपा, कांग्रेस व टीएमसी ने आधी आबादी का दिल तोड़ा: अन्नपूर्णा देवी

संवाददाता
देहरादून। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर रविवार को मां गंगा के जयकारों के बीच गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। कपाटोद्घाटन के साक्षी बने सैकड़ों लोगों ने मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि रविवार सुबह सात बजे भैरव घाटी स्थित प्राचीन भैरव मंदिर से मां गंगा की डोली यात्रा गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इस दौरान मुख्य ब्रह्म से मंदिर तक आर्मी के पाठ्य दंड और पारंपरिक ढोल-दमाकं एवं रणसिंघे की धुन पर झूमते श्रद्धालुओं के बीच मां गंगा की डोली



यात्रा 9 बजे अपने धाम गंगोत्री पहुंची। जहां डोली का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों और यात्रा कारोबारियों ने गंगा जी की डोली पर फूलों की बरसात की। इसके बाद यहां गंगा पूजन, गंगा सहस्त्रनाम, गंगा लहरी, श्रीशुक्त आदि के पाठ के साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान किया गया। जिसके बाद 12 बजकर 15 मिनट पर गंगोत्री मंदिर के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए।

संवाददाता
लखनऊ। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने संसद में नारी हित के प्रस्ताव को गिराकर आधी आबादी के दिल को तोड़ा है। सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने पर सपा समेत विपक्षी पार्टियों के सदस्य खुशी से तालियां बजा रही थीं। नारी विरोधी इस आचरण का खामियाजा सपा व कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रविवार को यहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं। पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी



आदित्यनाथ, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव व निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ संजय निषाद उपस्थित रहे। केन्द्रीय

महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक व सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। अब राजनैतिक रूप से सशक्त करने की बारी आयी और महिलाओं को

उनका अधिकार दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए बिल लाया गया तो इंडी गठबंधन के दलों ने इसके विरोध में वोटिंग की। इंडी गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता उनकी आदत में शुमार है।

इसके लिए आधी आबादी उन्हें माफ नहीं करेगी। नारी शक्ति अब जाग चुकी है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश में 50 वर्षों से ज्यादा समय कांग्रेस की सरकार रही उस समय ओबीसी को अधिकार देने से किसने रोका था। कांग्रेस आज ओबीसी के आरक्षण की बात करती है, जबकि मण्डल कमिशन की रिपोर्ट को वर्षों तक इन्होंने लोगों ने दबाकर रखा था। जबकि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी सरकार ने किया। सपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था।